भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1755
जिसका उत्तर 10 दिसंबर, 2025 को दिया जाना है ।
19 अग्रहायण, 1947 (शक)

डिजिटल कौशल पहल

1755. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डिजिटल पहुँच और रोजगार विस्तार हेतु डिजिटल इंडिया/भारतनेट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) डिजिटल कौशल पहलें कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या खजुराहो लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के कटनी, पन्ना और छतरपुर जिलों में भारतनेट फाइबर, अंतिम व्यक्ति तक वाई-फाई और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चालू हैं और कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो डिजिटल भुगतान, ई-बाजार और ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँच हेतु किसानों, महिलाओं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सक्षम बनाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि डिजिटल समावेशन कम रहता है, तो चिह्नित की गई बाधाओं का ब्यौरा क्या हैं और इसके समाधान हेतु क्या कदम उठाए जाने की योजना है; और

(ङ) उक्त जिलों में स्थानीय रोजगार सृजन और सूक्ष्म उद्यम अवसरों के साथ एमईआईटीवाई कौशल एवं उद्यमिता समर्थन को जोड़ने की रणनीति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ङ):** डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के उस दृष्टिकोण के अनुरूप शुरू किया, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करना और नागरिकों को सशक्त बनाना है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल तकनीकें प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुधार लाएँ, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार करें तथा देश में निवेश और रोजगार के अवसरों का सृजन करें।

भारतनेट

डिजिटल इंडिया ने भारतनेट जैसी पहलों के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस के तेजी से विस्तार में योगदान दिया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट प्रदान करना है।

पिछले 10 वर्षों में देश भर में इंटरनेट की पहुंच और उपयोग में काफी वृद्धि हुई है। अक्टूबर 2025 तक, भारतनेट के तहत 2,14,843 ग्राम पंचायतों (जीपी) को सेवा के लिए तैयार किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश की 17,850 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

खजुराहो शहर भारतनेट के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि भारतनेट कनेक्टिविटी केवल **ग्राम पंचायतों/गांवों** को प्रदान की जाती है।

कटनी और पन्ना जिलों में भारतनेट सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों का सारांश इस प्रकार है।

जिला	सेवा-तत्पर जीपी की संख्या
कटनी	115
पन्ना	387

डिजिटल कौशल और स्थानीय रोजगार क्षमता का विस्तार

भारत के डिजिटल परिवर्तन में कनेक्टिविटी के साथ-साथ डिजिटल स्किलिंग, रोजगार क्षमता और उद्यमिता शामिल है। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

फ्यूचरस्किल्स प्राइम प्रोग्राम

- ~41% महिलाओं सहित 15.5 लाख+ शिक्षार्थियों के साथ उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल के लिए राष्ट्रीय मंच
- उभरते तकनीकी डोमेन (एआई, क्लाउड, साइबर सुरक्षा, आदि) में रोजगार को सक्षम बनाता है।

नाईलिट डिजिटल साक्षरता और नौकरी से संबंधित प्रशिक्षण

- कटनी और पन्ना में 14 केंद्रों सहित देश भर में 9000+ नाईलिट केंद्र
- 43 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है
- सेमीकंडक्टर डिजाइन, साइबर सुरक्षा, फोरेंसिक, उद्योग 4.0 आदि में वर्चुअल लैब की स्थापना की और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के तहत क्रेडिट ट्रांसफर प्रदान करता है

पीएमजीदिशा (प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान)

- दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल साक्षरता पहलों में से एक
- बुनियादी डिजिटल साक्षरता के लिए प्रत्येक ग्रामीण परिवार से एक व्यक्ति को लक्षित किया गया
- देश भर में 6.39 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया (6 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले)

इंडियाएआई फ्यूचरस्किल्स

इसका उद्देश्य एआई डोमेन में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की संख्या में वृद्धि करके भारत में एआई कुशल पेशेवरों को विकसित करना है।

- 500 पीएचडी फेलो, 5,000 स्नातकोत्तर और 8,000 स्नातक का फैलोशिप लक्ष्य।
- नाईलिट के सहयोग से टियर-2 और टियर-3 शहरों में 27 इंडियाएआई डेटा और एआई लैब्स की स्थापना की गई
- एआई, डेटा और संबंधित क्षेत्रों जैसे डेटा एनोटेशन, डेटा क्यूरेशन, डेटा क्लीनिंग, डेटा साइंस आदि पर फाउंडेशन-स्तरीय पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं।
- 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 174 आईटीआई और पॉलिटेक्निक को अतिरिक्त इंडियाएआई डेटा और एआई लैब स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है

प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी)

यह देश भर में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करता है। पीएम-वाणी ढांचा स्थानीय उद्यमियों को न्यूनतम लाइसेंस आवश्यकताओं के साथ सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने में सक्षम बनाता है।

जिला	पीएम-वाणी हॉटस्पॉट*
कटनी	76
पन्ना	40

* (03.12.2025 तक)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

यह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। भावी उद्यमियों को गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है

इसके अलावा, योजना के तहत उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) लाभार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और इस प्रकार डिजिटल समावेशन और कौशल को सक्षम बनाया जाता है।
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, कई पहल हैं जो किसानों, महिलाओं, युवाओं और एमएसएमई को डिजिटल भुगतान, ई-मार्केट और ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाती हैं; जिनका विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत नागरिकों को डिजिटल भुगतान, ई-मार्केट और ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाने वाली प्रमुख पहल:

- **जेएएम ट्रिनिटी** (जन धन-आधार-मोबाइल) भारत सरकार की एक परिवर्तनकारी पहल है जिसे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, शासन में सुधार करने और कल्याणकारी लाभों और सार्वजनिक सेवाओं के कुशल वितरण को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है
- **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई):** यूपीआई ने देश भर में डिजिटल लेनदेन में क्रांति ला दी है। यूपीआई ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लाखों व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को तेज, सुरक्षित और कम लागत वाले डिजिटल भुगतान करने के लिए सशक्त बनाया है, जिससे वित्तीय समावेशन में काफी प्रगति हुई है।

यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरीशस सहित सात से अधिक देशों में लाइव है, जिससे भारत डिजिटल भुगतान में एक वैश्विक अग्रणी बन गया है।

· यूपीआई 49 करोड़ से अधिक व्यक्तियों, 6.5 करोड़ व्यापारियों को सेवा प्रदान करता है और 683 बैंकों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान प्रणाली बन जाती है।

· यूपीआई भारत के 85% डिजिटल भुगतान और वैश्विक वास्तविक समय के डिजिटल भुगतान के लगभग 50% को शक्ति प्रदान करता है।

- **आधार:** आधार दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान का कार्यक्रम है जो बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय-आधारित विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करता है। सितंबर, 2025 तक, अप्रैल 2022 में 126+ करोड़ के मुकाबले 143+ करोड़ आधार आईडी जनरेट की गई हैं।

प्रमाणीकरण लेनदेन की संख्या वित्त वर्ष 2022-23 में 2,291.97 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 2,707 करोड़ हो गई है, वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल से नवंबर 2025 की अवधि के लिए) में 1,768 करोड़ लेनदेन के साथ।

- **डिजिलॉकर:** डिजिलॉकर ने आम नागरिक के लिए मूल जारीकर्ता से प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक किसी भी समय पहुंच प्रदान की है। डिजिलॉकर की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए 61.29 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता इसके साथ पंजीकृत हैं और प्लेटफॉर्म पर 2261 जारीकर्ताओं से 835+ करोड़ से अधिक दस्तावेज जारी किए गए हैं।

यह संख्या अप्रैल 2022 में लगभग 507 करोड़ जारी किए गए दस्तावेजों और 10.65 करोड़ उपयोगकर्ताओं से बढ़ी है।

- **सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम):** जीईएम विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद को सक्षम बनाता है। इसमें 1.67 लाख से अधिक सरकारी खरीदार और 23 लाख+ विक्रेता और सेवा प्रदाता हैं।
- **सामान्य सेवा केंद्र –** सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) को एक उद्यमिता-आधारित और आत्मनिर्भर मॉडल के रूप में स्थापित किया गया है, जिसे सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया गया है।

सीएससी 2.0 परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को ई-सेवाएं प्रदान करना और सीएससी नेटवर्क को ग्राम पंचायत स्तर तक विस्तारित करना है, जो सरकारी, वित्तीय, आधार, शिक्षा, टेलीमेडिसिन, यात्रा और उपयोगिता सेवाओं सहित 800 से अधिक सेवाएं प्रदान करता है।
यह परियोजना मध्य प्रदेश राज्य सहित पूरे भारत में कार्यान्वित की गई है। सितंबर 2025 तक, देश भर में 5.69 लाख सीएससी कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 4.43 लाख ग्राम पंचायत स्तर पर हैं।

- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** डीबीटी सीधे कल्याणकारी भुगतान देने और नकली लाभार्थियों को हटाने के लिए आधार का उपयोग करता है।

अक्टूबर 2025 तक डीबीटी के माध्यम से 47+ लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जा चुके हैं। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का अधिकांश वितरण डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है।

- **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी):** यह मंच योजना के स्वामित्व वाले मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से आवेदनों को संसाधित करने और लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे छात्रवृत्ति/धन वितरित करने में सक्षम बनाता है।

अब तक, 13 मंत्रालयों/विभागों और 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित 153 योजनाओं को एनएसपी में शामिल किया गया है।

- **ई-ट्रांसपोर्ट:** ई-ट्रांसपोर्ट मिशन मोड परियोजना भारत के परिवहन क्षेत्र को एक केंद्रीकृत, राष्ट्रव्यापी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बदल रही है, जिसमें वाहन, सारथी और ई-चालान जैसे प्रमुख अनुप्रयोग शामिल हैं।
- **ई-संजीवनी -**ई-संजीवनी आपके स्मार्टफोन से सीधे डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों तक त्वरित और आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म ने स्पोक के रूप में कार्य करने वाले 1,36,525 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में 43.22 करोड़ से अधिक रोगियों की सेवा की है, जो 2,30,089 से अधिक डॉक्टरों, विशेषज्ञों, सुपर-विशेषज्ञों और टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा समर्थित हैं।
- **माईगव**: माईगव भारत सरकार का एक नागरिक जुड़ाव मंच है जो नीति निर्माण में लोगों को शामिल करने के लिए कई सरकारी निकायों/मंत्रालयों के साथ सहयोग करता है और सार्वजनिक हित और कल्याण के मुद्दों/विषयों पर लोगों की राय मांगता है।

वर्तमान में, 6.02+ करोड़ से अधिक नागरिक माईगव के साथ पंजीकृत हैं, जो अप्रैल 2022 में 2.33+ करोड़ उपयोगकर्ताओं के मुकाबले माईगव प्लेटफॉर्म पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं।

- **जीवन प्रमाण:** जीवन प्रमाण एक आधार बायोमेट्रिक-सक्षम डिजिटल सेवा है जो केंद्रीय, राज्य और अन्य सरकारी पेंशनभोगियों को आधार-आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके अपने घरों सहित भारत में कहीं से भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) आसानी से जमा करने की अनुमति देती है।

2014 से अब तक 11.69 करोड़ से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रों की प्रक्रिया की जा चुकी है।

- **ईताल** (इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन एकत्रीकरण और विश्लेषण परत) पर रिपोर्ट किए गए वार्षिक ई-लेनदेन वित्त वर्ष 2013-14 में 264 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 34,972 करोड़ हो गए हैं, जो भारत के तेजी से डिजिटल परिवर्तन को दर्शाता है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देना:** इस उप-योजना के अंतर्गत प्रमुख परियोजनाओं में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई), आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई), इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी और ईएमसी 2.0) योजना और इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीईसीएस) शामिल हैं।
- इन नीतिगत प्रयासों के परिणामस्वरूप, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण 19.5 प्रतिशत की सीएजीआर पर 2014-15 में 1.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 11.3 लाख करोड़ रुपये हो गया है और हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लगभग 24 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़कर 2024-25 में 3.26 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
- **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन):** एनकेएन राष्ट्रीय/राज्य डेटा केंद्रों (एनडीसी/एसडीसी), राज्य-व्यापी क्षेत्र नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन) के डिजिटल-ट्रैफिक को वहन करता है और विभिन्न डिजिटल इंडिया पहलों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करता है, और विभिन्न जी2जी (सरकार से सरकार) और जी2सी (सरकार से नागरिक) सेवाओं, जिला कनेक्टिविटी आदि के डिजिटल-ट्रैफिक को ले जाता है।

एनकेएन संसाधनों के आदान-प्रदान और सहयोगात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए हाई-स्पीड डेटा संचार नेटवर्क के माध्यम से देश भर के सभी ज्ञान संस्थानों को आपस में जोड़ता है।
वर्तमान में, एनकेएन के अंतर्गत संस्थानों के लिए 1,822 लिंक चालू और परिचालित किए गए हैं और 681 एनकेएन लिंक पूरे भारत में एनआईसी जिला केंद्रों से जुड़े हैं। इससे डिजिटल गवर्नेंस डेटा-ट्रैफ़िक को एनकेएन पर आसानी से संचालित किया जा सकेगा।

- **आईटी और आईटीईएस उद्योगों को बढ़ावा देना:** सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत बीपीओ संवर्धन योजना (आईबीपीएस) और पूर्वोत्तर बीपीओ संवर्धन योजनाएं शुरू कीं, जिसका उद्देश्य रोजगार के अवसर सृजित करना और छोटे शहरों/कस्बों में आईटी/आईटीईएस उद्योग का प्रसार करना है।इस योजना को पूरा कर लिया गया है।
- **समृद्ध (उत्पाद नवाचार, विकास और वृद्धि के लिए माइटी के स्टार्टअप एक्सेलरेटर)** कार्यक्रम के अंतर्गत, (पिछले तीन वर्षों में) पूरे भारत में 42 एक्सेलरेटर लगे हुए हैं।

स्थापना के बाद से, कार्यक्रम ने 373 स्टार्टअप को गति दी है और 201 स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

- **यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग) ऐप**: उमंग सभी भारतीय नागरिकों को केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों और अन्य नागरिक केंद्रित सेवाओं तक अखिल भारतीय ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक एकल मंच प्रदान करता है।

उमंग अब 240 केंद्र और राज्य सरकार के विभागों द्वारा दी जाने वाली 2,363 सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है, जो 9.60 करोड़ पंजीकृत नागरिकों के बढ़ते उपयोगकर्ता आधार को सेवा प्रदान करता है।

*****